

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1947 / 2013 / बीकानेर

मैसर्स चौधरी एक्सक्वेटर एण्ड इलाईड सर्विसेज,  
पुरानी शिवबाड़ी रोड, बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

- (i) सहायक आयुक्त,  
कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, बीकानेर ।  
(ii)उपायुक्त (प्रशासन), बीकानेर ।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री शफी मोहम्मद चौहान,  
अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,  
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक :29.05.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील उपायुक्त, (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे “सक्षम अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की है, जो प्रकरण क्रमांक प.4(206)कर/34/उपा-बी/2013–14/2259 दिनांक 07.08.2013 के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा-34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को “सक्षम अधिकारी” द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, बीकानेर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 61 व 55 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2007–08 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2011, पारित कर, मांग राशि रु.2,70,231/- सृजित की गयी थी, के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी संख्या-2 “सक्षम अधिकारी” के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी “सक्षम अधिकारी” द्वारा सुनवायी कर, आदेश दिनांक 07.08.2013 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये बिना ही घोषित संव्यवहार में वृद्धि कर, करारोपण कर, एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत

अपील संख्या -1947 / 2013 / बीकानेर

एवम् उचित नहीं है। अग्रिम अभिवाक् किया कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना बाध्यकारी है। अतः न्याय हित में सुनवायी का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी ताकि इस संबंध में सुनवायी की जाकर, विधिसम्मत एवम् सही निर्धारण आदेश पारित किये जा सके। तदनुसार, सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना कर, प्रकरण को संबंधित निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया ।

5. विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का मूल निर्धारण आदेश शून्य मांग में दिनांक 05.05.2009 को पारित किया गया था। तदउपरांत वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर-तृतीय, जयपुर द्वारा निर्धारण अधिकारी को सूचित किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स जीटीएल इण्डिया (प्रा.) लि., जयपुर को रु.1556173/- का माल विक्रय कर, वैट रु.79477/- वसूल कर, राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। कथन किया कि अंपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में किये गये उक्त संव्यवहार को छुपाकर, करापवंचन किया गया है। तथापि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 26,55 व 61 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व सुनवायी हेतु नोटिस जारी किया गया था परन्तु नियत तिथि को अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। कथन किया कि रिकॉर्ड पत्रावली पर जारी नोटिस उपलब्ध है। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित एवम् विधिक रूप से निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एकपक्षीय निर्धारण आदेश की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनज़र ही “सक्षम अधिकारी” द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है जो कि पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः न्याय हित में एक और मौका प्रदान करने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहंस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। विद्वान अभिभाषक ने दिये गये तर्कों में स्पष्ट किया है कि सर्वोत्तम कर निर्धारण करने से पूर्व व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में, बाध्यकारी है विशेषतः कर निर्धारण में समुचित तथ्यों के आधार पर ही दायित्व बढ़ाया जा सकता है। दायित्व बढ़ाने पर सुनवायी का अवसर दिये जाने के नैसर्गिक पक्ष से कठइ

✓

अपील संख्या -1947 / 2013 / बीकानेर

इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि परन्तु हस्तगत प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

अधिनियम की धारा 34.—Reopening of *ex parte* assessment. — (1)

Where an assessment has been made *ex parte* under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

(3) Where the order for cancellation of the assessment under sub-section (1) has been passed, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, shall make fresh assessment within sixty days from the communication of the order passed by the Deputy Commissioner (Administration) under sub-section (1).

7. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानानुसार दो बिन्दु निर्णयक हैं जिनके आधार पर पारित कर निर्धारण आदेश को पुनः खोला जा सकता है—(i) उपर्युक्त वर्णित धाराओं में पारित निर्धारण आदेश हेतु व्यवहारी को सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अथवा (ii) सूचना पत्र प्राप्त तो हो गया हो परन्तु सूचना पत्र की पालना न करने के समुचित कारण विद्यमान हों। उक्त प्रावधानों के प्रकाश में, रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2009–10 के संबंध में निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व विधिक रूप से सुनवायी हेतु नोटिस तो जारी किया गया है (रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ कमांक-5 पर मौजूद) परन्तु उक्त तामिलशुदा नहीं है। जिसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि जारी नोटिस अपीलार्थी व्यवहारी को तामिल हो गया था। अतः जारी नोटिस को



अपील संख्या –1947 / 2013 / बीकानेर

अपीलार्थी व्यवहारी को तामिलशुदा नहीं माना जा सकता। अतः, उक्त तथ्यात्मक स्थिति व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के दृष्टिगत प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2011 एवम् “सक्षम अधिकारी” द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2013 अपास्त किञ्चन करते हुये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश नियमानुसार पारित करना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी व्यवहारी से यह अपेक्षित है कि आलोच्य अवधि से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष वक्त निर्धारण प्रस्तुत करें। अपीलार्थी व्यवहारी के अनुपस्थित रहने की दशा में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

8. परिणामतः, प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

५९.५.२०१५  
(मदन लाल)  
सदस्य